(ख) क्या सरकार द्वारा इन अभिकरणों को वीडियो कैसेटों में फिल्मों के साथ-साथ विभिन्न कम्पनियों के विज्ञापनों को रिकार्ड/प्रदर्शित करने के लिए कोई लाइसेंस दिए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) ऐसी कोई जानकारी अपेक्षित नहीं है ।

विवरण

फिल्मों के वीडियो कैसेटों का निर्माण करने वाली एजेंसियों के बारे में सरकार द्वारा न तो कोई आंकड़े रखे जाते हैं और न ही इस प्रकार की फिल्मों के भाषावार ब्यौरों का संचय और रखरखाव किया जाता है । तथापि इन कामों के लिए यूनिटों के पंजीकरण की एक स्कीम मई, 1988 में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी :—

1. फिल्मों की प्रतिकृतियों का वीडियो अंतरण करना ;

2. पूर्व रिकार्ड किए गए वीडियो कैसेटों का अनुलिपिकरण/निर्माण करना तथा

3. वीडियो से फिल्मों में प्रतिकृतियों का अंतरण करना । इन गतिविधियों के लिए अब तक 38 यूनिट पंजीकृत किए गए हैं।

Reduction in consumer Price index for Industrial Workers

*89. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether there has been a sudden reduction in the Consumer Price Index for Industrial Workers after the introduction of the 1982 series; and

(b) whether the organisations of workers and trade Unions have made complaints regarding the reduction in Dearness allowance in spite of the rise in prices?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) and (b) The Consumer Price Index only reflects the movement in the prices of items which figure in the relevant consumption basket.

The new series of Consumer Price Index for industrial workers (base 1982-100) was introduced effective from the month of October, 1988. The Index numbers for the 5 months, October, 1988—February, 1989 are as follows:

October, 1988	—	167
November, 1988	—	168
December, 1988	—	166
January, 1989	—	165
February, 1989	—	165

Representations have been received from some workers' organisations pointing out the decline in the Index Number for the month of December, 1988 as compared to November, 1988. A monthly period is not a satisfactory basis for tracking changes in the Consumer Price Index. As will be seen, between October, 1988 and February, 1989 there has been a change of only 2 points in the new Index, which is accounted for mainly by seasonal factors, such as the decline in the prices of many food items.

The rates of dearness allowance vary from industrial unit to unit, depending on the agreements in force between managements and trade unions. As has been pointed out above, there has not been a rise in prices for many items figuring in the Consumer Price Index between December, 1988 and February, 1989.

Setting up of Consumer Courts

*90. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government have urged States and Union Territories to quickly set up consumer courts;

(b) whether Government have provided any help to the State Governments in setting up such courts; and

(c) if so, the details thereof and by when such courts are likely to be set up and to what extent the grievances arising out of consumer's interest are likely to be solved?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM): (a) Government has urged the States to set up the Consumer Disputes Redressal agencies envisaged under the Consumer production Act, 1986.

(b) and (c) Under the Act, Central Government is responsible for setting up National Consumer Disputes Redressal Commission, which has been set up. The responsibility for setting up Consumer disputes Redressal Commission (State Commission) and the Consumer Disputes Redressal Forums (District Forums) rests with the State Governments/Union Territories. Several States have already set up these bodies, and the Central Government have requested the others to do so early. The Planning Commission has agreed to include 'Consumer Protection', including the implementation of the Consumer Protection Act, 1986, as a Plan item in the Seventh Five Year Plan.

The Consumer Protection Act, 1986 provides simple, speedy and inexpensive redressal to the consumers against defective goods and services, unfair trade practices, etc. The redressal is provided by way of replacement, refund of price, removal of defects, or compensation.

दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने वाले वाणिज्यिक प्रसारणों पर नये सिरे से विचार किया जाना

*91. **श्री कपिल वर्मा :**

श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने वाले वाणिज्यिक प्रसारणों पर नये सिरे से विचार करने के लिए निकट भविष्य में विशेषज्ञों का एक पैनल बनाने का विचार रखती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या दूरदर्शन के बढ़ते प्रभाव के कारण फिल्म उद्योग की सत्ता समाप्त हो जाने का खतरा है; और

(ग) क्या सरकार को फिल्म उद्योग से जुड़े व्यक्तियों से केबल टी० वी० के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। समिति आकाशवाणी/दूरदर्शन में प्रसारित होने वाले वाणिज्यिक विज्ञापनों की जांच करेगी और विज्ञापनदाताओं की समस्याओं को हल करने के लिए तथा अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापनों से आय बढ़ाने, विज्ञापनों के स्तर को सुधारने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और आकाशवाणी/दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए कोड के अनुरूप आकाशवाणी/दूरदर्शन के सभी चैनलों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखते हुए ठोस सिफारिश करेगी। समिति के अध्यक्ष सचिव (सूचना और प्रसारण) होंगे और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा विज्ञापन उद्योग के प्रमुख संगठनों, बड़े और लघु उद्योगों तथा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के भी प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।

(ख) सरकार को फिल्म उद्योग पर टेलीविजन के प्रभाव के किसी वैज्ञानिक अध्ययन की जानकारी नहीं है।